

ब्रिटि"ा शासन काल के दौरान अलवर रियासत में औद्योगिकीकरण

सुमन गोयल

सहायक आचार्य; इतिहास

रामेश्वरी देवी कन्या महा वद्यालय भरतपुर ;राजस्थान

सामान्यतया यह विचारधारा प्रचलित रही है कि राजस्थान प्राचीन काल से ही अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कमजोर रहा है और मुगलों के पतन के बाद मराठों के आक्रमणों ने तो राजस्थान को कंगाली के द्वार पर ही जा खड़ा किया। कैम्ब्रिज इतिहासकारों वि"ीषतः टॉड व उसके अनुयायियों का मूल उद्दे"य ही 1818 से पूर्व की स्थिति को आर्थिक अव्यवस्था तथा विना"ा का समय बता अंग्रेजी प्रश्रय को राजस्थान की आर्थिक प्रगति का श्रेय देना था। कर्नल टॉड इस आर्थिक अव्यवस्था के सिद्धान्त का जनक था तथा जिन राज्यों में ऐसा नहीं था वहां राजनीतिक कु"ासन, कुप्रबन्ध, जागीरदारों के अत्याचार व व्यापारिक प्रगति में कृत्रिम बन्धनों को उत्तरदायी ठहराया। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत रही। राजनीतिक अव्यवस्था, अराजकता व उथल-पुथल के बावजूद 1818 से पूर्व का समय अधिका"ा राज्यों के लिये आर्थिक सम्पन्नता का युग था। उद्योग धंधों, व्यापार वाणिज्य के लिये आव"यक सभी अनुकूल परिस्थितियाँ खनिज सम्पदा, कच्चा माल, सस्ता श्रम, पूंजी, व्यापारिक मार्गों के कारण सामान्यतया आर्थिक अव्यवस्था संतोषजनक थी। इस समय बड़े उद्योग तो बहुसंख्यक थे नहीं किन्तु कुटीर व लघु उद्योग अपनी विकसित अव्यवस्था में थे जिनके उत्पादों का मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही रूपों में काफी महत्व था। वैणसी द्वारा लिखित "परगने री विगत" से ज्ञात होता है कि प्रत्येक गाँव में अलग-अलग जाति के लोग रहा करते थे, जो अपने जातीय धंधे के माध्यम से गाँव की आव"यकताओं की पूर्ति करते थे।" (1) पर कम्पनी के आगमन के प"चात् यहाँ की अर्थव्यवस्था का दोहन प्रारम्भ हो गया। परन्तु यह दोहन ब्रिटि"ा अर्थव्यवस्था के समानान्तर हुआ। जैसे-जैसे ब्रिटि"ा अर्थव्यवस्था विकसित होती रही उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहा लगभग उसी आधार पर यहाँ की अर्थव्यवस्था का शोषण भी हुआ। प्रारम्भ अंग्रेजी वाणिज्यवाद के चलते कम्पनी का स्वरूप पूर्णतः व्यापारिक रहा। इस समय उसका उद्दे"य भारतीय उत्पादित वस्तुओं को खरीद कर उन्हें विदे"ों में ऊँची कीमत पर बेचना था। चूंकि इस समय तक कम्पनी की राजनीतिक शक्तियाँ भी सीमित प्रायः थी। अतः राजपूताने के सभी राज्य राजनीतिक उथल-पुथल (मराठों व सामन्तों के कारण) के बावजूद भी उद्योग धंधों की दृष्टि से सम्पन्न थे। अलवर भी इसका अपवाद नहीं था। कृषि इतर उद्योगों के विकास के कारण ही 1872 में अलवर की मात्र 48.32 प्रति"ात जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी।² इस समय प्रचलित प्रमुख उद्योगों का विवरण निम्नानुसार है—

सूती वस्त्र उद्योग:— स्थानीय मांग तो पूरा करने की दृष्टि से मोटे सूती कपड़े की बुनाई का काम तो राजस्थान में लगभग प्रत्येक गाँव में होता था। अलवर में मलमल बनाने का सर्वोत्तम काम प्रारम्भ में मुस्लिम महिलाओं द्वारा किया जाता था किन्तु बाद में यह कार्य कोल्हियों द्वारा किया जाने लगा। अलवर राज्य के गोविन्दगढ़, कठूमर, तिजारा, लक्ष्मणगढ़, बहादुरपुर, वस्त्र उद्योग के प्रमुख केन्द्र थे।³ यहाँ की पगड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध थीं। लगभग 3000 परिवार पगड़ी बनाने का कार्य से रोजगार पाते थे। सूती कपड़ों की रंगाई व छपाई का उद्योग भी काफी व्यापक था। अतः रंगरेज व छीपा वर्ग का महत्व स्वतः ही बढ़ा। रंगाई के लिये लकड़ी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था। अलवर, राजगढ़, प्रतापगढ़ व नारायणपुरा रंगाई व छपाई के लिये प्रसिद्ध थे।⁴ बहुसंख्यक लोग इस व्यवसाय में व्यस्त थे तथा अलवर की एक गली रंगभरियों की गली कहलाती थी।⁵

19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में रेलवे का विकास के बाद राजस्थान से रूई के निर्यात व विदेशों की कपड़े के आयात से हाथ से कते व बुने कपड़े के उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसका असर अलवर के वस्त्र उद्योग पर भी पड़ा तथा धीरे-धीरे इस उद्योग में गिरावट आने लगी।

चर्म उद्योग:— यातायात के साधनों के अभाव के कारण यह उद्योग मात्र स्थानीय मृत पशुओं के चमड़े तक ही सीमित था। प्राप्त चमड़े से जूते, बैग, पानी की चरस आदि बनाए जाते थे। इस्माइलपुर, राजगढ़, अलवर आदि चर्म उद्योग के प्रमुख केन्द्र थे।⁶

काष्ठ उद्योग:— घरेलू उद्योग धंधों में काष्ठ का स्थान काफी महत्वपूर्ण था। अधिकांशतः कृषि उपकरण लकड़ी के ही होते थे। मकानों के निर्माण में भी काष्ठ उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान था। खाटें, फर्नीचर, तथा साज सज्जा का समान लकड़ी से बनाया जाता था। 19 वी सदी के अंत में विद्यालयों, अस्पतालों व अन्य संस्थानों के विकास के साथ ही फर्नीचर की माँग बढ़ने लगी। इससे काष्ठ उद्योग विकसित हुआ।

लुहारी उद्योग:— राजस्थान के लुहार अस्त्र-शस्त्र तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बनाने में दक्ष थे। घरेलू सामान यथा कढ़ाई, कुन्दा, सांकल, चिमटा आदि बनाने के अलावा कृषकों द्वारा बनाये जाने वाले औजार जैसे फावड़ा, खुरपा, बैलगाड़ी के धातु के हिस्से आदि भी बनाये जाते थे।

पत्थर उद्योग:— बलुआ पत्थर व संगमरमर से संबंधित नक्काशी के कार्य में अलवर का महत्वपूर्ण स्थान था। इन शिल्पकारों के प्रमुख उत्पाद ओखली, कूड़े, प्याली, आटा पीसने की चक्की, चूना पीसने की लोड़ी, कोल्हू, पानी की टंकी, होद (हौज) आदि। इनके अलावा नक्काशीदार जालियाँ, खिड़की, दरवाजे, रौशनदान, खम्भे, मेहराव आदि। पत्थर के कार्य के प्रमुख केन्द्र राजगढ़, थानागाजी, बहरोर, अलवर, खेरली आदि थे।⁷

तेलधानी:— तिल, सरसों व अलसी में से तेल निकालना एक प्रमुख उद्योग था। जो कि तेली वर्ग का वंशानुगत व्यवसाय था। तेलधानी से प्राप्त तेल का उपयोग प्रकाश करने में व खाद्यान्न तेल के रूप में किया जाता था।

नमक उद्योग:— पुराने समय से राजस्थान में नमक उद्योग के कई केन्द्र थे जो स्थानीय माँगों की पूर्ति के साथ-साथ आस-पास के प्रदेशों की माँग भी पूरी करते थे। राज. का नमक बनारस, संयुक्त प्रांत व अवध में जाता था। आज शायद यह बात आश्चर्यजनक लगे कि कभी अलवर में भी नमक उत्पादन होता था। अलवर में नमक खारे पानी को संग्रहित कर बनाया जाता था। 1877 ब्रिटिश सरकार ने अलवर राज्य के साथ संधि की जिसके द्वारा स्थानीय नमक का उत्पादन बंद हो गया। बदले में अंग्रेजी सरकार ने अलवर को 1 लाख 25 हजार रुपये देना स्वीकार किया।⁸ पर इस नमक समझौते के चलते नमक व्यवसाय से जुड़े लोग बेरोजगार हो गए व नमक उत्पादन में मात्रात्मक गिरावट आई।

मीनाकारी:— अलवर एवं अन्य राजधानी के नगरों के स्वर्णकार एवं रजतकार राज्यों के संरक्षण में उच्चतम कुशलता प्राप्त थे। इनके द्वारा निर्मित सोने चांदी के जेवर मौलिकता लिये हुए थे। राजपूताना गजेटियर में इनकी पुनः प्रशंसा करते हुए लिखा है कि " राजपूताना की ये कलाएँ अतिसंवेदनशील एवं मौलिक है किंतु यूरोप की नकल पर आधारित कलकत्ता व बम्बई से आयतित नमूनों के आगमन से इनके अभिलोपन या विनाश का खतरा सन्निकट है।"⁹

धातु गलाने की भट्टी:— 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राजगढ़, टेहला, बालेटा में लगभग धातु गलाने की 30 भट्टियाँ थी।¹¹ परन्तु विदेगी धातु की प्रतिस्पर्धा में आने के बाद यह उद्योग ठप्प हो गए। 19 वीं सदी के उत्तरार्द्ध में यह निजी निवेशकों को सौंप दिया गया।

अन्य उद्योग:— इन सब उद्योगों के अतिरिक्त अलवर में हाथी दांत को तराने का कार्य किया जाता था। अलवर हाथी दांत की चूड़ियां बनाने में प्रमुख था। इसके अलावा शतरंज की मोहरें, मेज सजाने की चीजें, लघु हाथी, ऊंट, घोड़े गाड़ियों आदि का निर्माण भी होता था।

अलवर में चीनी मिट्टी एवं कांच के बर्तनों का निर्माण होता था। ये बर्तन इतने पतले थे कि इन्हें कागजी बर्तन कहा जाता था। इनका दिल्ली में निर्यात होता था। इस तरह अलवर अपने उद्योगों के विकास की दृष्टि से लगभग आत्मनिर्भर था। चूंकि राजनीतिक दृष्टि से भी अभी तक ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त प्रायः था। अतः उद्योगों का विकास संभव था।

उद्योगों के पतन के कारण:— परन्तु 18 वीं सदी के प्रारम्भ में इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति होने के बाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद का स्वरूप लगभग बदल गया। अब उसे आवयकता थी एक ऐसे उपनिवेश की जो कच्चे माल की प्राप्ति व तैयार माल की खपत का केन्द्र बन सके। इस दृष्टि से सम्पूर्ण भारत पर राजनीतिक नियंत्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई और साथ ही प्रारम्भ हो गई लघु एवं कुटीर उद्योगों के विनाश की प्रक्रिया ताकि इंग्लैण्ड के उद्योगों से उत्पादित सामग्री को कोई प्रतिस्पर्धी न मिल सके। इसके लिये ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासकों पर कई प्रतिबंध लगाए।¹²

01. ब्रिटिश सरकार ने 1891 में एक आदेश द्वारा देशी राज्यों एवं ब्रिटिश भारत के पूंजीपतियों के मध्य सीधे सम्पर्क पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना कोई देशी राज्य अथवा ब्रिटिश भारत के नागरिक धन का लेनदेन नहीं कर सकते थे। कोई ब्रिटिश अथवा यूरोपीय नागरिक देशी राज्यों में उद्योग लगाते तो उन्हें ब्रिटिश सरकार की अनुमति आवयक थी। इस व्यवस्था में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को ही खत्म कर दिया।¹³

02. अन्तर्राज्यीय ऋण भी अंग्रेजी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लिये जा सकते थे और राज्य सरकार सार्वजनिक ऋण पत्र भी बिना अंग्रेजी सरकार की अनुमति के प्रसारित नहीं कर सकती थी।

03. भारतीय राज्यों के आद्योगिकीकरण के संबंध में 1893 ई. में भारत सरकार ने राज्यों को स्पष्ट कर दिया था कि यदि कोई राज्य अपनी जनता के आर्थिक सहयोग से कोई कारखाना स्थापित करना चाहे तो इसके लिये उसे ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेने की आवयकता नहीं रहेगी। परन्तु यदि कारखाना स्थापित करने में ब्रिटिश अथवा यूरोपीय विप्रेषकों एवं तकनीकियों के सहयोग की बात हो तो उस राज्य को इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा भारत सरकार को देना आवयक होगा।¹⁴ इस प्रकार की नीति के फलस्वरूप अलवर के औद्योगिक विकास में बाधाएँ उत्पन्न हुईं।

ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के अतिरिक्त उद्योगों के पतन के अन्य कारण थे:—

04. रियासतों के राजा जो यहाँ उत्पादित विलासिता की सामग्री, मीनाकारी, हाथीदांत व कलात्मक वस्तुओं के खरीददार थे उन्होंने भी पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर इनकी अवहेलना करनी शुरू कर दी। जिससे अनेक लोगों की आय का स्रोत बने ये उद्योग पतन की ओर अग्रसर हो गए।

05. कुटीर उद्योगों के संबंध में सामन्ती नीति भी इन उद्योगों के विना का कारण बनी। राजा व सामन्तों ने शिल्पकारों व कुटीर उद्योगों पर अनेक कार थोप दिये जिससे ये व्यवसाय अलाभकारी बन गए। जैसे— झोपड़ी—लाग, तेली धाणी लाग, खातियों से खाट, किवाड़ी लाग एवं लगड़ी बिचौती, सुनारों से हांसिल सोना चांदी एवं जरी सितारा, चमारों से लाग चरस लाग, पाउन, बिचौती, मुड्डा एवं नारी ढोरी, पिनारों से कार कंडे, बुनकरों से रेजी लाग, खटीकों से ऊन खटीकान, लुहारों से लोहा मंडारी आदि कर वसूले गए। इन सबसे स्थानीय माल विदेगी माल से महंगा हो गया तथा आपसी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया।
06. इसके अलावा सामन्ती व्यवस्था उद्योगों का विरोध इस कारण भी करती है क्योंकि उद्योग नवीन सामाजिक एवं आर्थिक शक्तियों को जन्म देते हैं। जो सामन्तवाद के लिये चुनौती है।
07. उपनिवेशवाद भी औद्योगिक पिछड़ेपन पर ही फलता-फूलता है। अतः सामन्तवाद व उपनिवेशवाद दोनों उद्योग विरोधी व्यवस्थाओं के मध्य स्थापित सहयोग ने औद्योगिक पिछड़ेपन को और बढ़ाया। यहाँ के राजा लालची थे वे तुरंत लाभ चाहते थे। अतः उन्होंने पत्थरों, खनिजों, कपास, चमड़ा, ऊन आदि के निर्यात से प्राप्त आय को महत्व दिया यदि इन पर आधारित उद्योगों की स्थापना होती तो उन्हें भय था कि उनके कच्चे माल के निर्यात में होने वाली आय समाप्त हो जाएगी।
08. यहाँ विशाल उद्योगों की संभावनाओं के बावजूद तकनीकी पिछड़ेपन के कारण यह संभव नहीं हो सका। विदेगी तकनीकी का आयात संभव नहीं था ऐसी स्थिति में औद्योगिक पिछड़ापन बढ़ता ही चला गया।

इस विऔद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप बरोजगारी बढ़ी। उद्योगों में लगे हुये लोग अब अन्य क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसर ढूढने लगे परिणामस्वरूप कृषि पर नित्य प्रति बोझ बढ़ता ही चला गया। 1872 में अलवर की मात्र 48.32 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी जो 1931 में बढ़कर 72 प्रतिशत हो गई। इससे कृषि पर बोझ बढ़ा जिसका अनुभव पैतृक कृषकों ने किया और इसके विरुद्ध आन्दोलन छेड़ दिया कृषक आन्दोलन के रूप में।

उद्योगों के पतन के साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी अवरुद्ध हो गया। विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग समाप्त प्रायः हो गया, व्यापारिक क्रियाओं का पतन हो गया, धन निष्कासन की प्रक्रिया तीव्र हो गई।

औद्योगिकीकरण:— 20 वीं शताब्दी के आरम्भ में ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने एक बार फिर करवट बदली। औद्योगिक क्रांति के अतिरिक्त उत्पादन के परिणामस्वरूप धनार्जन कर सम्पन्न बने पूजीपति पूंजी निवेश की दिशा में अग्रसर हुए और एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिससे सीमित मात्रा में भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई क्योंकि भारत ब्रिटिश पूजीपतियों के लिये पूंजी निवेश का आकर्षक केन्द्र था जहाँ सस्ता-श्रम, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध था। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों ने इस प्रक्रिया को तीव्र कर दिया। अलवर में भी इस समय औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। 20 वीं शताब्दी के तीसरे दशक के आरम्भ में राज्य सरकार ने पंजाब राज्य के उद्योग धंधों के निदेशक श्री रामलाल को राज्य की औद्योगिक उन्नति की संभावनाओं पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित किया।¹⁵ 1933 में उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिससे उन्होंने रूई उद्योग बढ़ाने (1925-26 में रूई का उत्पादन 33945 मन था जो 6 वर्ष बाद 1931-32 में सिर्फ 2070 मन रह गया)¹⁶ पर जोर दिया, बांधों के पास की जमीन पर गन्ना बोने की सिफारिश की जिससे गुड़ खाण्डसारी सारी उद्योग का विकास हो सके। थानागाजी को इसके लिये

उपयुक्त बताया गया। उनके अनुसार पंजाब की अपेक्षा अलवर में लाख उद्योग के विकास की अधिक संभावनाएं थी क्योंकि अलवर में वनों में ढाक, बेरी, खैर, पीपल, कीकर, लाख के कीड़े आसानी से पाले जा सकते हैं।¹⁷ सरसों के निर्यात की जगह अलवर में ही तेल उद्योग से साबुन उद्योग का विकास भी हो सकता था।¹⁸ बेराइट्स के उपयोग से पेन्ट बनाने का कारखाना और केओलिन, फेल्सपार, क्वार्ट्ज आदि के उपयोग से पॉटरी का कारखाना चालू करने का सुझाव भी उन्होंने दिया। मगर उनके प्रतिवेदन के एक दशक तक अलवर में औद्योगिक विकास का कोई प्रयत्न हीं हुआ। इस दशक में कुछ कल-कारखाने खुले अव्य पर राज्य सरकार के द्वारा नहीं।

1928 में श्री काशीराम गुप्ता ने मंगत बॉस (तहसील मण्डावर) में स्लेट पत्थर की खान में कार्य शुरू किया।¹⁹ 1933-34 में आज की तहसील के पीछे श्री जादूराम ने पहली तेल लगाई।²⁰ 1935-36 में रामनारायण ब्रादर्स ने स्टोन चिप्स व पीली मिट्टी पीसने का कारखाना शुरू किया।²¹ 1937 ई. में हीरा आइस फैक्टरी शुरू हुई। 1941 में हीरा आइस फैक्टरी के साथ हीरा ऑइल मिल भी काम करने लगी।²¹ 1943 में एक और बड़ी मिल रानीबाला ऑयल मिल बनी।²²

1940-41 में अलवर के रेल्वे स्टेशन पर खनिज पदार्थ पीसने का पहला आधुनिक कारखाना लगा जो आज गोपाल मिनरल्स के नाम से चल रहा है।²³ हीरा आइस मिल व रानीबाला ऑइल मिल अब काल के पर्दे में छिप गई। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज ने 1928-30 में राज्यों के विकास के लिये कुछ स्वायत्ता की मांग की। लेकिन बटलर कमेटी के समक्ष कुछ आर्थिक अधिकार प्रस्तुत किए लेकिन उन अधिकारों की मांग राज्यों के आर्थिक विकास के स्थान पर राजाओं की आर्थिक स्वायत्ता के लिये थी। चैम्बर ने किसी ऐसे सामान्य दावे को प्रस्तुत नहीं किया जिसमें उन आर्थिक प्रतिबन्धों को हटाने की मांग की गई हो जिनसे राज्यों का विकास रूका हुआ था। इसके स्थान पर इन राज्यों ने भारत सरकार से सीमा शुल्क की आय में राज्यों को हिस्सा देने के लिये कहा।²⁴ इसलिए बटलर कमेटी ने नरेन्द्र मण्डल ने अव्य औद्योगिकीकरण की अव्यकता अनुभव की लेकिन राज्यों का प्रशासन राजा की आज्ञा पर इतना निर्भर करता था कि निष्क्रमण किए हुये व्यापारियों को राज्य में पूंजी निवेश का उत्साह ही नहीं हुआ। कुछ राज्यों ने अव्य अपने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की अलवर भी उनमें से एक था। एक औद्योगिकीकरण का एक प्रयास मात्र था।

अलवर राज्य की ओर से औद्योगिक उन्नति का पहला प्रयत्न 1943 ई. में हुआ। उस समय श्री बापना अलवर राज्य के प्रधानमंत्री थे। वे औद्योगिक उन्नति की ओर विशेष ध्यान देते थे। रेल्वे स्टेशन के आगे फैली हुई जमीन पर उन्होंने एक औद्योगिक बस्ती की स्थापना की। इस औद्योगिक बस्ती में रामनारायण ब्रादर्स को 150 बीघा जमीन बहुत कम दाम पर दी गई। रामनारायण ब्रादर्स ने ज्वाइट स्टॉक कम्पनी के रूप में अलवर पेन्ट एवं वार्निंग फैक्टरी स्थापित की।²⁴ शीघ्र ही औद्योगिक बस्ती में एक सूती मिल की इमारत भी बनने लगी। कुछ दिनों बाद पोर्सलीन फैक्ट्री भी काम करने लगी व होजरी तथा माचिस मिल भी चालू हो गई।²⁵ मगर श्री बापना के जाने के साथ अलवर की औद्योगिक उन्नति का सपना भी चला गया। उनके जाने के बाद सूती मिल की अधूरी इमारत अधूरी ही रह गई, पेन्ट, वार्निंग फैक्ट्री असफल हो गई। दूसरा फैक्ट्रियों भी बन्द होने लगी।

01. डॉ. माँगीलाल व्यास 'मयंक'जोधपुर राज्य का इतिहास, पृ. 238
02. आर.ए.आर. 1871-72, पृ. 192-194, जैन, डॉ. एम.एस. आधुनिक राजस्थान का इतिहास, पृ.234
03. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर-अलवर, पृ. 268
04. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर-अलवर पृ.269
05. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर-अलवर पृ.269
06. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर-अलवर पृ. 270
07. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर-अलवर पृ. 270
08. दि इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, जिल्द 12 पृ.-130-131
09. दि इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, जिल्द 3 पृ.-240-241
10. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर-अलवर पृ.272
11. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर-अलवर पृ.272
12. पो. कन्सलटेशन, इन्टरनल बी.दिसम्बर 1891, नं. 161-171, भारत सरकार की ग"ती चिट्ठी नं. 81, बीकानेर, फॉरेन पोलिटिकल नं. 1-बी, 175, 1941-44, पृ. 16
13. शर्मा, डॉ. ब्रजकि"ोर, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, पृ. 322
14. 1893 के सरक्यूलर का संदर्भ पो. क. 1929, फाईल नं. 170/आर./19 से लिया गया है।
15. "विनय" अलवर अंक संपादक-डॉ. नीरजसिंह, पृ.226
16. "विनय" अलवर अंक संपादक-डॉ. नीरजसिंह, पृ.226
17. "विनय" अलवर अंक संपादक-डॉ. नीरजसिंह, पृ.227
18. "विनय" अलवर अंक संपादक-डॉ. नीरजसिंह, पृ.227
19. "विनय" अलवर अंक संपादक-डॉ. नीरजसिंह, पृ.227
20. "विनय" अलवर अंक संपादक-डॉ. नीरजसिंह, पृ.227
21. "विनय" अलवर अंक संपादक-डॉ. नीरजसिंह, पृ.227
22. "विनय" अलवर अंक संपादक-डॉ. नीरजसिंह, पृ.227
23. दि ब्रिटि"ा काउन एण्ड इण्डियन स्टेट्स लंदन (कोई तिथि नहीं) पृ. 80-120। यह प्रतिवेदन बटलर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जैन, डॉ. एम.एस. आधुनिक राजस्थान का इतिहास, पृ. 242
24. "विनय" अलवर अंक संपादक डॉ. नीरजसिंह, पृ.227